membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting. Accordingly, the condition precedent to the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council is that the Legislative Assembly of that State should pass a Resolution to that effect in the manner prescribed. The article does not provide for advice by the Government of India. The Constitution of Jammu and Kashmir does not provide for the abolition of the Legislative Council, much less for advice by the Government of India.

Bye-elections to Lok Sabha

1002. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many by-elections for the Lok Sabha have been held during 1978-79 and how many by-elections are due and the steps taken to fill-up the Lok Sabha vacancies and the election schedule finalised if any: Lok Sabha Constituency-wise and the reasons for delay in announcing the election schedule; and

(b) whether the Election Commission have received complaints regarding the irregularities/malpractices reported to have been committed during the conduct of these bye-election, nature of complaints received and the action taken constituency-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) During 1978-79, 11 bye-elections have been held to the Lok Sabha. At present 4 seats are vacant and bye-elections are required to be held to fill the same. Two statements containing necessary information are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3878/79].

टेलीविजन कार्यक्रमों को तैयार किया जाना

1003. श्री रामराम शाक्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम विभाग में ही तैयार किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अच्छे कार्यक्रम बड़े अन्तराल के बाद ही दिखाये जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने के कार्य अन्य देशों की भांति, गैर सरकारी एजेन्सियों को देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख). फिलहाल टेलीकास्ट किए जाने वाले लगभग 79.3% कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रमों की लोकप्रियता और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों की अनुपूर्ति करने के लिए उन गैर सरकारी एजेंसियों/व्यक्तियों, जो अच्छे दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता रखते हैं, को भी कार्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा जाता है।

दिल्ली में कम्पनियों को इस्पात की सप्लाई

1004. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रतिमास 10 टन अथवा इससे भी अधिक इस्पात की सप्लाई की जाती है ;

(ख) किस उद्देश्य से इसकी सप्लाई की जाती है और क्या इसका उचित उपयोग किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात काले बाजार में बेचा जाता है और जिस उद्देश्य से यह सप्लाई किया जाता है उसके प्रयोग में यह नहीं आता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) इस प्रकार की जानकारी एकत्र करने में काफी समय और श्रम लगेगा जो इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, यदि विशेष इकाइयों की विशेष अवधि के बारे में जानकारी चाहिए तो प्रस्तुत की जा सकती है।